भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 4072
गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024/28 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

क्षेत्रीय संपर्क का विकास

4072. श्री ई. तुकारामः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कर्नाटक में, विशेष रूप से बेल्लारी जिले में उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) वर्ष 2024 के दौरान नए हवाई अड्डों के विकास, हवाई यातायात बुनियादी ढांचे में वृद्धि और कर्नाटक के टियर-2 और टियर-3 शहरों में उड़ान संचालन में वृद्धि में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में विमानन क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त राज्य में हवाई अड्डों और एयरलाइन संचालन में टिकाऊ विमानन ईंधन और अन्य पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) योजना एक मांग चालित योजना है, जिसमें एयरलाइन प्रचालक किसी विशेष मार्ग पर परिचालन की व्यवहार्यता का आकलन करते हैं और समय-समय पर योजना के अंतर्गत बोली लगाते हैं। एयरलाइनों का चयन पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। 'उड़ान' योजना के प्रावधानों के अनुसार, असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार/उन्नयन वैध बोली के माध्यम से उनकी पहचान करके और एसएओ (चयनित एयरलाइन प्रचालक) को अवार्ड करके किया जाता है। 'उड़ान' योजना के अंतर्गत उड़ानों के प्रचालन के लिए कर्नाटक राज्य में दस (10) अल्पसेवित और असेवित हवाईअड्डों अर्थात् बीदर, मैसूर, विद्यानगर, हुबली, कलबुरगि, बेलगाम, शिवमोग्गा, विजयपुरा, करवाड़ा और बलदोटा (कोप्पल) की पहचान की गई है, जहां (3) नामत: बलदोटा (कोप्पल), विजयपुरा और करवाड़ा को छोड़कर सभी का प्रचालन शुरू हो चुका है।

(ग) और (घ): नागर विमानन मंत्रालय ने सभी परिचालित हवाईअड्डों, जो अनुसूचित परिचालनरत हैं, और आगामी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकासकर्ता को कार्बन तटस्थता और नेट जीरो प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने की सलाह दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हरित ऊर्जा का उपयोग भी शामिल है। वर्ष 2014 से अब तक कुल 80 हवाईअड्डों ने 100% हरित ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु हवाईअड्डे ने एयरपोर्ट इन्टरनेशनल काउन्सिल (एसीआई) का उच्चतम कार्बन मान्यता स्तर 5 प्राप्त किया है, जबकि दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद हवाईअड्डों ने स्तर 4+ एसीआई मान्यता प्राप्त की है। ये हवाई अड्डे कार्बन-तटस्थ हो गए हैं।

नागर विमानन मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत एयरस्पेस के लचीले उपयोग (एफयूए) की अवधारणा को पूरी तरह से लागू करके राष्ट्रीय एयर स्पेस के इष्टतम उपयोग का सुझाव दिया है। इससे सभी रिपोर्टिंग एयरलाइनों को उड़ान समय और ईंधन उपयोग में महत्वपूर्ण बचत के माध्यम से लगभग 868.1 करोड़ रुपए की संचयी बचत हुई है और साथ ही 01 अगस्त 2020 से कार्बन (CO2) उत्सर्जन में 188538.5 टन से अधिक की संचयी कमी आई है।

******